मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता की सरकार है और हमारा एकमात्र ध्येय जनता की सेवा है, ऐसे में विधायक मुखर होकर काम करें।

'हैरिटेज, नाइट, ग्रामीण व ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट के लिये बजट में प्रावधान किये गये हैं'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने विधायक दल की बैठक में मंत्रियों को अगले दो दिन जिलों में जाने के निर्देश दिये

जयपुर, 21 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने विधायकों से कहा कि राज्य सरकार द्वारा विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए जनकल्याणकारी एवं शानदार बजट प्रस्तुत किया गया है। हमारी सरकार प्रत्येक वर्ग के सशक्तीकरण के लिए निरंतर काम कर रही है। हम सभी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक बजट घोषणा का जमीन पर लाभ आमजन को मिले। शर्मा ने कहा कि आगामी 2 दिन (शनिवार-रविवार) सभी प्रभारी मंत्री एवं प्रभारी सचिव अपने प्रभार वाले जिलों में जाएंगे तथा बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

■ **मुख्यमंत्री ने विधायकों को भी अपने क्षेत्र में कई बार बजट घोषणाओं का प्रचार-प्रसार करने व आमजन की समस्याओं का निस्तारण करने के लिये कहा।**

उन्होंने कहा कि विधायक भी अपने क्षेत्रों में रहकर बजट घोषणाओं का प्रचार-प्रसार करें तथा आमजन की समस्याओं का निस्तारण भी करें। उन्होंने विधायकों को स्पष्ट तौर पर कहा कि हमारी सरकार जनता की सरकार है और हमारा एकमात्र ध्येय जनता की सेवा है, ऐसे में विधायक मुखर होकर काम करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के लिए चार लाख सरकारी नौकरियों के वादे को पूरा करने की दिशा में आगामी वर्ष में सवा लाख पदों पर सरकारी भर्तियां निकाली जायेंगी तथा निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष में डेढ़ लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार ग्रीन बजट पेश किया गया है। इस बजट में किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ा कर 9 हजार रूपए करने, गेहूं के एमएसपी पर 150 रूपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस देने, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में बीमित पशुपालकों की संख्या को दोगुना करने सहित, विभिन्न घोषणाएं की गई हैं।

उन्होंने कहा कि पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए हेरिटेज पर्यटन, नाइट टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए बजटीय प्रावधान भी किये गये हैं। इस दौरान, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, मंत्रीगण तथा विधायकगण मौजूद थे।

ब्यावर में अवैध खनन पर 2.82 करोड़ रूपए का जुर्माना

ब्यावर, 21 फरवरी (निसं)। जिला कलेक्टर डॉ. महेन्द्र खड़गावत के निर्देशानुसार, अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के तहत खनिज विभाग ने ग्राम रावतमाल, तहसील ब्यावर,

■ **जिला प्रशासन तथा खनन विभाग की सख्त कार्यवाही से अवैध खनन पर अंकुश लगेगा।**

जिला ब्यावर में स्थित खनन पट्टा संख्या 311/2007 (खनिज क्वार्ट्ज एवं फेल्सस्पार) का औचक निरीक्षण एवं सर्वे किया।? निरीक्षण के दौरान, मौके पर खनन कार्य बंद पाया गया, लेकिन पट्टा क्षेत्र में तीन खनन पिट्स मिले, जिनकी पैमाइश करने पर पता चला कि इन पिट्स से लगभग 21,341 टन खनिज का उत्खनन किया जा चुका है। खनिज विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, पट्टाधारी मैसर्स मातृपिता अर्थ प्रोडक्ट द्वारा अब तक कुल 44,877 टन खनिज का निर्गमन किया गया था, जबकि सर्वेक्षण में पाया गया कि खदान से मात्र 21,341 टन खनिज ही निकाला गया था। इससे स्पष्ट होता है कि पट्टाधारी ने खनन क्षेत्र का दुरुपयोग कर अन्य अवैध स्रोतों से प्राप्त खनिज का निर्गमन किया है। इस अनियमितता को ध्यान में रखते हुए पट्टाधारी के विरुद्ध रवन्ना दुरुपयोग का केस बनाकर दो करोड़ बयासी लाख तैंतालीस हजार एक सौ अट्ठाईस रुपये की मांग हेतु नोटिस जारी किया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। जिला प्रशासन एवं खनिज विभाग द्वारा की गई इस सख्त कार्रवाई से अवैध खनन पर अंकुश लगने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है।

पुष्कर नगर परिषद का जेईएन 2 लाख रूपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार

पुष्कर/अजमेर, 21 फरवरी (कासं)। अजमेर के पुष्कर उपखंड में शुक्रवार को भीलवाड़ा एसीबी ने ट्रैप की कार्यवाही करते हुए, पुष्कर नगर परिषद में कार्यरत जूनियर इंजीनियर रामनिवास मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी जेईएन रामनिवास मीणा ने टेंडर प्रक्रिया में बिल पास करने की एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। सूत्रों के अनुसार रिश्वत की राशि आरोपी का रिश्तेदार लेकर फरार हो गया है। एसीबी की टीम फरार रिश्तेदार की तलाश में जुटी है। दूसरी टीम नगर परिषद से मामले से जुड़ी जानकारियां एकत्र कर रही है। एसीबी अधिकारी आरोपी से पूछताछ में जुटे हैं।

एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम ने शुक्रवार को पुष्कर में कार्रवाई की। टीम ने जेईएन रामनिवास मीणा पुत्र रतीराम मीणा, जो दौसा जिले के खेड़लीकला गांव का निवासी है, और नगर परिषद पुष्कर जिला अजमेर में कनिष्ठ अभियंता है, को गिरफ्तार किया। उसने परिवादी से पुष्कर नगर परिषद क्षेत्र में किए गए कार्यों के भुगतान बिलों पर हस्ताक्षर करने तथा बिल आगे एईएन व कमिश्नर को फॉरवर्ड करने के लिये वर्तमान बिलों तथा पूर्व में भुगतान हो चुके बिलों की कुल राशि का दस प्रतिशत मांगा। यह कुल राशि 20.83 लाख रुपए थी, इसलिए उसने दो लाख मांगे थे। यही नहीं, उसने एईएन मुकेश चौहान के लिए भी 5 प्रतिशत राशि (60 हजार) मांगी।

■ **जेईएन ने रूपये अपने चचेरे भाई को दिलाये और वो मौके से रिश्वत की राशि लेकर फरार हो गया।**

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रविप्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि मांग सत्यापन के बाद, 16 फरवरी को रामनिवास ने 2 लाख रूपये रिश्वत स्वयं ली तथा 50 हजार रुपए सहायक अभियंता मुकेश चौहान को दिलवाए, जो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर में एपीओ हैं। रामनिवास मीणा ने शुक्रवार को रिश्वत राशि के साथ परिवादी को पुष्कर बुलाया तथा रिश्वत राशि अपने चचेरे भाई महेश मीणा को दिलवाई, जो रिश्वत की राशि लेकर भाग गया। एसीबी टीम और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि एसीबी भीलवाड़ा प्रथम को शिकायत मिली थी कि परिवादी से कार्यों के भुगतान से संबंधित बिलों पर हस्ताक्षर करने और आगे एईएन व कमिश्नर को फॉरवर्ड करने के लिए 2.60 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है। इस पर एसीबी अजमेर रेंज के उपमहानिरीक्षक कालुराम रावत के सुपरविज़न में एसीबी भीलवाड़ा टीम के पारसमल उप अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा प्रथम ने ट्रैप कार्यवाही की।

'दिल्ली रेलवे ..

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यात्रियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तभी स्पेशल ट्रेनों के लेट होने और प्लेटफॉर्म बदलने की घोषणा के चलते स्टेशन पर भगदड़ मच गई थी। इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी। जबकि 15 लोग घायल हुए थे।

दो -भाषा नीति का पालन करेगा तमिलनाडु

चेन्नई, 21 फरवरी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यानी कि एनईपी से जुड़े विवादों के बीच, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पर हमला करने को लेकर डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने बड़ा बयान दिया है। उदयनिधि ने शुक्रवार को केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पर पलटवार करते हुए कहा कि तमिलनाडु सिर्फ 'दो-भाषा' नीति का पालन करेगा और वह हमेशा से 'तीन-भाषा नीति का विरोध करता रहा है'। उन्होंने कहा कि राज्य केंद्र से केवल अपने द्वारा दिए गए टैक्स में से अपना जायज़ हक मांग रहा है।

■ **तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को दो टूक जवाब दिया।**

उदयनिधि ने कहा, 'हम अपना हिस्सा, करीब 2150 करोड़ रुपये मांग रहे हैं। केंद्र चाहता है कि हम एनईपी और 'तीन भाषा' नीति को स्वीकार करें। तमिलनाडु हमेशा से तीन भाषा नीति का विरोध करता रहा है, इसलिए इसमें राजनीति करने की क्या बात है? शिक्षा तमिलों का अधिकार है, कृपया समझें कि राजनीति कौन कर रहा है।' इससे पहले दिन में, प्रधान ने एनईपी लागू करने पर जारी विवाद को लेकर स्टालिन पर निशाना साधा और उन पर 'राजनीतिक विमर्श बनाए रखने के लिए प्रगतिशील सुधारों को खतरे में डालने' का आरोप लगाया।

स्टालिनको लिखी चिट्ठी में प्रधान ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर युवा शिक्षार्थियों के हितों के बारे में सोचना चाहिए, जिन्हें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से फायदा होगा। शिक्षा मंत्री स्टालिन द्वारा गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र का जवाब दे रहे थे।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने तमिलनाडु के मु.मंत्री स्टालिन को चिट्ठी लिखी

प्रधान ने स्टालिन से शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं करने का आग्रह किया

नयी दिल्ली, 21 फरवरी। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के रूख की आलोचना करते हुए उनसे शिक्षा का राजनीतिकरण न करने तथा छात्रों के हित में राजनीतिक मतभेदों से उपर उठकर निर्णय लेने को कहा है। प्रधान ने स्टालिन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विरोध किये जाने पर शुक्रवार को एक पत्र लिखकर यह हिदायत दी।

केन्द्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर यह पत्र साझा करते हुए कहा , किसी राज्य द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अदूरदर्शी दृष्टिकोण से देखना तथा राजनीतिक आख्यानों को बनाये रखने के लिए धमकियों का उपयोग करना अत्यधिक अनुचित है।

सरकार विश्व स्तर पर शाश्वत तमिल संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने तथा लोकप्रिय बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मैं विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि शिक्षा का राजनीतिकरण न करें तथा हमारे छात्रों के सर्वोत्तम हित में राजनीतिक मतभेदों से उपर उठें। प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री पहले भी कह चुके हैं कि सरकार तमिल भाषा और संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, तमिल भाषा शाश्वत है और तमिल संस्कृति वैश्विक है। सरकार तमिल भाषा और संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

■ **प्रधान ने कहा, केन्द्र सरकार दुनिया भर में तमिल संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।**

उन्होंने कहा कि सरकार की किसी भी राज्य या समुदाय पर कोई भी भाषा थोपने की मंशा नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाषाई स्वतंत्रता के सिद्धांत को कायम रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि छात्र अपनी पसंद की भाषा में सीखना जारी रखें। वास्तव में, इस नीति का एक मुख्य उद्देश्य तमिल सहित भारतीय भाषाओं के शिक्षण को पुनर्जीवित और मजबूत करना है, जिन्हें दशकों से औपचारिक शिक्षा में धीरे-धीरे दरकिनार कर दिया गया है।

उन्होंने तीन-भाषा नीति के महत्वपूर्ण बिंदु का जिक्र करते हुए कहा कि यह 1968 से भारत के शिक्षा ढांचे की रीढ़ रही है। दुर्भाग्य से, लगातार शिक्षा नीतियों का हिस्सा होने के बावजूद, इसे कभी भी अक्षरशः लागू नहीं किया गया, जिससे स्कूलों में भारतीय भाषाओं के व्यवस्थित शिक्षण में गिरावट आई। समय के साथ, इसका परिणाम विदेशी भाषाओं पर अत्यधिक निर्भरता के रूप में सामने आया है, जिससे छात्रों का अपनी भाषाई जड़ों से संपर्क सीमित हो गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस ऐतिहासिक चूक को सुधारने का प्रयास करती है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि तमिल सहित हर भारतीय भाषा को शिक्षा में उसका उचित स्थान मिले। उल्लेखनीय है कि स्टालिन ने तीन भाषा के फार्मूले को लेकर सवाल उठाये हैं।

महाकुंभ में नहाती महिलाओं के वीडियो बनाकर बेचे जा रहे हैं

नई दिल्ली, 21 फरवरी। गुजरात पुलिस ने महाकुंभ में नहाती महिलाओं के वीडियो बनाकर बेचने के मामले में प्रयागराज के यूट्यूबर सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर इस तरह के वीडियो यूट्यूब और टेलीग्राम पर अपलोड करने का आरोप है। छानबीन में इनके पास से महिलाओं के आपत्तिजनक फुटेज मिले हैं।

दरअसल, गुजरात पुलिस राजकोट स्थित एक अस्पताल में महिलाओं के चेकअप के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए जाने के मामले की जांच कर रही थी। इसी सिलसिले में उसने महाराष्ट्र के लातूर से प्रज्वल अशोक तेली और सांगली से राजेंद्र पाटिल को गिरफ्तार किया। इन दोनों से पूछताछ के आधार पर प्रयागरात के यूट्यूबर चंद्रप्रकाश फूलचंद को गिरफ्तार किया।

■ **गुजरात पुलिस ने प्रयागराज के यू ट्यूबर सहित तीन को गिरफ्तार किया है।**

■ **गुजरात पुलिस जब राजकोट के अस्पताल में महिलाओं की जांच के वीडियो यू ट्यूब पर अपलोड करने के मामले की जांच कर रही थी तब उसे प्रयागराज के वीडियो की जानकारी मिली।**

अहमदाबाद साइबर अपराध पुलिस उपायुक्त लवीना सिन्हा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी चंद्र प्रकाश ने कुछ महीने पहले सीपी मोंडा नाम से एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था जिस पर उसने महाकुंभ में स्नान कर रही महिला तीर्थयात्रियों के वीडियो अपलोड किए थे। चंद्र प्रकाश को बुधवार को प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर टेलीग्राम एप पर सब्सक्राइबर्स से पैसे कमाने के उद्देश्य से महिला मरीजों के आपत्तिजनक वीडियो अपलोड करने का आरोप है।

सिन्हा ने बताया कि जबकि तेली और पाटिल ने हैकर्स के जरिए महिला मरीजों के वीडियो हासिल किए थे। वहीं चंद्र प्रकाश ने अन्य यूट्यूब चैनलों से वीडियो डाउनलोड किए और हाल ही में उन्हें अपने चैनल पर अपलोड किया था। हम जांच कर रहे हैं कि क्या उसका भी इन वीडियो को बेचने का इरादा था। तीनों आरोपियों को 1 मार्च तक पुलिस हिरासत में रखा गया है।

कांग्रेस ने पलटवार किया...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सवालों की बौछार करते हुये, कांग्रेस नेता ने कहा, "अगर मोदी सरकार यू.एस.ए.आई.डी. को "अछूत" मानती है तो उसने स्वच्छ भारत मिशन के लिये उसका सहयोग क्यों लिया। अमेरिका ने इस मिशन के अंतर्गत, 73 नगरों में भारत सरकार के साथ काम किया किया। फरवरी 2022 में, अटल इनोवेशन मिशन तथा नीति आयोग ने यू.एस.ए.आई.डी. के साथ, "समृद्ध" योजना के अंतर्गत, नई साझेदारी की घोषणा क्यों की थी, जिसका उद्देश्य सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा को बेहतर बनाना था?

खेड़ा ने मोदी सरकार से यह भी पूछा कि सरकार ने 2021 में 1000 लाख डॉलर से अधिक कोविड-19 सहायता प्राप्त करने के लिये अमेरिकन सरकार से "अनेक बार" अनुरोध क्यों किया था? खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस भारत में यूएस एड फंडिंग पर "श्वेत पत्र" जारी करने की माँग कर ही चुकी है।

उन्होंने कहा, यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि हम वैश्विक साझेदारी, विकास एजेंसियों तथा यूएस एड जैसे सहायता-तंत्रों को अनैतिक नहीं मानते। यह भाजपा है जिसने डीपस्टेट की कहानी शुरु की थी और भाजपा ने ही सबसे पहले यूएस एड को दुष्ट कहा था। उन्होंने कहा, लेकिन हमारे पास ऐसे पर्याप्त प्रमाण हैं कि आरएसएस-भाजपा विदेशी एजेंसियों से गुप्त सहायता लेती आ रही है, ताकि भारतीय लोकतंत्र को अस्थिर किया जा सके तथा हमारे संविधान को कमजोर एवं नष्ट किया जा सके।"

इस विवादास्पद मुद्दे पर कांग्रेस की "श्वेत पत्र" जारी करने की माँग पर मोदी सरकार तथा भाजपा की खामोशी यह साफ-साफ दर्शा रही है कि सत्तारूढ़ पार्टी की रूचि इन संदेहों की सफाई देने के बजाय, इस विवाद को बनाये रखने में अधिक है, क्योंकि उसकी रणनीति विपक्ष को बदनाम करने की है।

एक पद सुरक्षित रख ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

के आधार पर योग्यता तय की जायेगी। उन्होंने अदालत को बताया कि एकबारीय उपाय के रूप में फार्मेसी पद पर भर्ती न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक एवं व्यवसायिक परीक्षा में प्राप्त अंकों और बोनस अंको के जोड़कर वरीयता सूची के आधार पर होगी।

सुनील कुमार सिंगोदिया ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने 5 मई 2023 को नया भर्ती विज्ञापन जारी कर कहा कि अभ्यर्थियों का चयन प्रोफेशनल योग्यता व उनके अनुभव के अंकों के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने अदालत को बताया कि नियमानुसार परीक्षा में सीनियर सैकेण्डरी में प्राप्त अंक एवं डिप्लोमा एवं फार्मेसी में प्राप्त अंको को जोड़कर वरीयता सूची बनानी थी, लेकिन विभाग ने केवल डिप्लोमा एवं फार्मेसी एवं बोनस अंकों के आधार पर वरीयता सूची जारी की है। इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि भर्ती विज्ञापन, सेवा नियमों की निर्धारित चयन प्रक्रिया के विपरीत नहीं हो सकता।

जब चयन नियमों में सीनियर सेकेंडरी एवं प्रोफेशनल योग्यता व अनुभव के अंकों के आधार पर मेरिट बनाने का नियम है तो भर्ती विज्ञापन में भी इस नियम के पालन में ही योग्य अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जानी चाहिए। इससे पहले के भर्ती विज्ञापन में भी मेरिट लिस्ट सीनियर सेकेंडरी व प्रोफेशनल योग्यता के अंकों को जोड़कर बनाने का प्रावधान किया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने 11 दिसंबर, 2023 को चयन सूची जारी करने पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। इस मामले की अंतिम सुनवाई 25 मार्च 2025 को होगी।

दहेज के लिये विवाहिता की हत्या कर भूसे में जलाया

धौलपुर, 21 फरवरी। दहेज की खातिर एक और विवाहिता बलि चढ़ी है। जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के नुनाहेरा गांव में 23 साल की विवाहिता की हत्या कर डेड बॉडी को भूसा में जलाने का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। पुलिस ने चिता से अस्थियां सबूत के लिए कब्जे में ली हैं। मृतका के भाई ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

मृतका नीरज पत्नी कमल किशोर के भाई मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि करीब 5 वर्ष पूर्व बहन नीरज की शादी नुनहेरा गांव निवासी कमल किशोर के साथ संपन्न हुई थी। उस समय, हैसियत के मुताबिक शादी में दान दहेज दिया था। लेकिन ससुराल पक्ष के लोग दहेज की अतिरिक्त मांग करने लगे। दहेज के लिए बहन से मारपीट भी की।

कई मर्तबा समाज के पंच-पटेलों को लेकर समझाइश करने की भी कोशिश की गई। लेकिन ससुराल पक्ष के लोग नहीं माने और बहन नीरज से आए दिन मारपीट करते रहे। भाई ने आरोप लगाते हुए कहा गुरुवार को भी बहन से मारपीट की गई थी। बहन ने मायके फोन कर हम लोगों को बुलाया था। भाई का आरोप है कि वे पिता भगवान सिंह के साथ ससुराल पहुंचे तो पाया कि बेटी की हत्या कर लाश को भूसा में जला दिया गया था। पूरे घटनाक्रम से स्थानीय पुलिस को अवगत कराया गया।

■ **विवाहिता के भाई ने मामला दर्ज कराया, पुलिस ने चिता से अस्थियाँ एकत्रित कीं**

मौके पर थाना प्रभारी वीरेन्द्र सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे । चिता से पुलिस ने साक्ष्य के लिए अस्थियां एकत्रित की हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि पिता ने दहेज हत्या का आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया है। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले के हर बिंदु पर गहनता से जांच कर रही है। मामले में कानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा।

'यूएस एड फंडिंग मामले में कांग्रेस अपने दुष्कर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है'

भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर राष्ट्रहित के विरोध में काम करने का आरोप लगाया

नयी दिल्ली, 21 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तथाकथित फैक्ट चेकरों और कांग्रेस द्वारा अमेरिका के यूएसएड एड को भारत के बजाय बंगलादेश भेजे जाने का प्रचार किये जाने की निंदा करते हुए शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस अपने दुष्कर्मों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने यहां पार्टी के केन्द्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस और संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के देश विरोधी बयानों और कार्यों को सबूतों के साथ पेश करते हुए प्रश्न उठाए। भाटिया ने कहा कि गांधी ऐसे कृत्य इसलिए करते हैं क्योंकि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से नफरत करते-करते भारत और इसके नागरिकों से भी नफरत करने लगे हैं।

भाटिया ने कहा, लोकसभा चुनाव से पूर्व भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ-साथ कई देश प्रेमी पत्रकारों और संगठनों ने यह बात उठाई कि विदेशी शक्तियां भारत की चुनावी प्रक्रिया में यह सोच के हस्तक्षेप करती हैं कि कैसे देश का गौरव एवं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी को सत्ता से हटाया जाए।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में देश में जो स्थिरता आई है, उसे आज पूरा विश्व और भारत की जनता देख रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को यह पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें भ्रष्टाचार और दलाली की आदत पड़ चुकी है। अगर कोई यह मानता है कि कांग्रेस पार्टी और गांधी केवल मोदी से नफरत करते हैं, तो यह आधा सच है। वास्तविकता यह है कि वह हर उस भारतीय नागरिक से नफरत करते हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक सशक्त सरकार चुनता है।

■ **भाटिया ने कहा, विदेशी शक्तियां देश के गौरव तथा विश्व के लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदी को सत्ता से हटाना चाहती हैं इसलिए चुनाव में हस्तक्षेप कर रही हैं।**

भाजपा प्रवक्ता ने कहा, जिन तथाकथित फैक्टचेकरों के तार गांधी परिवार से जुड़ते हैं उनका काम फैक्ट चेक करना नहीं है, बल्कि केवल राहुल गांधी के झूठ को सत्य बताकर आगे बढ़ाना है। इसीलिए आज सुबह से ही गांधी परिवार के फैक्टचेकर यह बताने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं कि 2.1 करोड़ डॉलर का भारत से कोई लेना देना नहीं है। आज कई ऐसे गंभीर प्रश्न हैं, जो यह साबित करते हैं कि राहुल गांधी देश से गद्दारी करते हैं और उनकी चुप्पी का केवल एक ही निष्कर्ष है कि राहुल गांधी ने कसम भले ही संविधान की ली हो लेकिन मन ही मन वो ठान चुके हैं कि उन्हें भारत के लोकतंत्र को कमजोर करना है।

भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि हाल ही में एक और तथ्य सामने आया है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के उप-नेता गौरव गोगोई की पत्नी के आतंकी संगठन आईएसआई से कथित लिंक उजागर हुए हैं। एक जिम्मेदार पार्टी के नाते भाजपा ने गोगोई से इस पर स्पष्टीकरण मांगा था कि क्या उनकी पत्नी ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी के साथ काम किया है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला।

भाटिया ने कहा, अगर संक्षेप में कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि "कांग्रेस का हाथ, देश के दुश्मनों के साथ।" इसके प्रमाण हैं, अंकल सोरोस से कांग्रेस का संबंध, कांग्रेस का चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से पार्टी-टू-पार्टी एमओयू, सैम पित्रोदा का चीन को दुश्मन न मानना, सोनिया गांधी का एफडीएलएपी का अध्यक्ष होना, गौरव गोगोई की पत्नी से जुड़े तथ्य, राहुल गांधी का इल्हान उमर से मिलना और मणिशंकर अय्यर का पाकिस्तान से मदद मांगना। आज पूरा देश समझ चुका है कि राहुल गांधी मोदी जी से नफरत में किसी भी देशविरोधी गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, चाहे उससे भारत को नुकसान ही क्यों न हो। जब भी उनसे इन विषयों पर जवाब मांगा गया, उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। लेकिन भाजपा अब भी इन गद्दारों से जवाब की उम्मीद करती है क्योंकि देश की जनता यह जवाब चाहती है।

एस.आई. भर्ती...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि जिसमें कहा गया है कि 'पेपर लीक' का अगर व्यापक प्रभाव नहीं हो, और जांच से यह सिद्ध ना हो पाएं कि परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों का बड़ा हिस्सा या बहुसंख्यक हिस्सा 'पेपर लीक' से प्रभावित नहीं था, तो इन मामले में पूरी परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता।

अदालत के आदेश अनुसार अगले दो महिने भी एस.आई. भर्ती परीक्षा को लेकर जांच जारी रहेगी और अगर 'पेपर लीक' प्रकरण में लिप्त पाये गये अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि हुई तो अदालती कानूनों की कई मिसालें सामने हैं जो परीक्षा को रद्द करने के तर्कों को मजबूत करती है।

वर्तमान में 850 चयनित अभ्यर्थियों में से लगभग 55 को जांच के बाद गिरफ्तार किया गया है, और इनमें से कुछ को जमानत भी मिल गई है।

सभी पक्षों को सुनने और उनकी सहमति से अदालत ने राज्य सरकार को मामले में निर्णय करने के लिए दो माह का समय देते हुए मामले की सुनवाई 2 मई को तय की है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908